इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2125

30 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए

नई इस्पात प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

2125. श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेल बोर्ड ने वर्ष 2008 में बिहार के बेतिया, माहनार और गया, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, उज्जैन और ग्वालियर, असम के गुवाहाटी, उत्तर प्रदेश के लखिमपुर, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 10 इस्पात प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक आधार पर स्वीकृति प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो इन इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ये कब से कार्य करना शुरू कर देंगी ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क): से (ग) : जी, हां। 10 इस्पात प्रसंस्करण इकाइयां (एसपीयू) ऐसी हैं जिनके लिए सेल बोर्ड ने वर्ष 2007 से 2009 के दौरान सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया था।

इन इस्पात प्रसंस्करण इकाइयों (एसपीयू) की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

इस्पात प्रसंस्करण इकाइयों का नाम (एसपीयू)	वर्तमान स्थिति
बिहार	
बेतिया	उत्पादन शुरू हो गया है।
गया	इस परियोजना के लिए 27.3 एकड़ कृषि भूमि अर्जित की गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)/बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) ने औद्योगिक उपयोग के लिए कृषीय भूमि को परिवर्तित करने का मामला उठाया है।

जारी/-

माहनार	भूमि की सतह गहरी है और इसके लिए काफी मात्रा में लैंड फिलिंग की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है और इसकी समीक्षा की जा रही है।
मध्य प्रदेश	संयुक्त उद्यम आधार पर स्थापित की जा रही हैं।
होशंगाबाद	
उज्जैन	
ग्वालियर	
उत्तर प्रदेश	
लखीमपुर	
हिमाचल प्रदेश	
कांगड़ा	कांगड़ा में एसपीयू इंडियन वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट के अधिसूचित भूमि/क्षेत्र की सीमा में आता है। इस अधिसूचित सीमा का विस्तार करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ मामला उठाया गया है। फरवरी, 2012 में स्थल पर कार्य रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई थी।
जम्मू एवं कश्मीर	
श्रीनगर	जम्मू एंव कश्मीर सरकार ने नवंबर, 2011 में राज्य की औद्योगिक नीति के अनुसार एसपीयू के लिए वांछित रियायतें और लाभ प्रदान कर दिए हैं। परियोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
असम	
गुवाहाटी	भूमि का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। बांउड्री पर तार-बाड़ बिछाने, प्रवेश द्वार और सिक्युरिटी रूम का कार्य पूरा कर लिया गया है। असम सरकार से रियायते और लाभ प्रतीक्षित हैं। परियोजना की समीक्षा की जा रही है।

****